खबरें

आप तक

RNI : MAHHIN/2003/10991

वर्ष - 24 अंक -07 मुंबई, सोमवार ०२ मार्च से ०८ मार्च २०२६ पृष्ठ : 4 कीमत : 1 रुपये

78 वर्षीय व्यक्ति 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटाले में 1.16 करोड़ रुपये का शिकार : मामला दर्ज

मुंबई : मुलुंड के 78 वर्षीय निवासी को कथित तौर पर साइबर जालसाजों ने 1.16 करोड़ रुपये का चूना लगाया। इन जालसाजों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की धमकी दी।

पीड़ित, थॉमस मैथ्यू पुलिक्कोटिल (78), जो एक फैब्रिकेशन केमिकल कंपनी के सेवानिवृत्त निदेशक और मुलुंड (पश्चिम) निवासी हैं, अपनी पत्न ी टेस्ला (72) के साथ रहते हैं। उनकी शिकायत के अनुसार, यह घटना 26 दिसंबर, 2025 और 24 फरवरी, 2026 के बीच घटी।

पुलिक्कोटिल ने बताया कि 26 दिसंबर, 2025 को सुबह लगभग 9 बजे, उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ''विजय खन्ना'' बताया और दावा किया कि वह जेट एयरवेज के प्रमोटर नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा सीबीआई अधिकारी है। कॉल करने वाले ने पुलिक्कोटिल को झूठी सूचना दी कि उनके नाम से कैनरा बैंक में एक खाता खोला गया है और इसका इस्तेमाल 2 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में किया गया है। उन्हें बताया गया कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इसके बाद धोखेबाज ने प्रदीप सावंत, राजेश और रविकुमार

नाम के अन्य कथित ''सीबीआई अधिकारियों'' का परिचय कराया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय नंबरों सहित विभिन्न मोबाइल नंबरों से पीड़ित से संपर्क किया। आरोपियों ने अपने दावों को वैध दिखाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से सीबीआई के नाम और लोगो वाले जाली दस्तावेज भी भेजे।

पीड़ित को कथित धोखाधड़ी की राशि का 80 प्रतिशत ''सुरक्षा जमा'' के रूप में जमा करने का निर्देश दिया गया और उन्हें कड़ी गोपनीयता बनाए रखने की चेतावनी दी गई। गिरफ्तारी और जान से मारने की धमकी के डर से, पुलिक्कोटिल और उनकी पत्नी ने मुलुंड स्थित अपने एचडीएफसी बैंक खातों से आरोपियों द्वारा दिए गए कई बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी।

शिकायत के अनुसार, पुलिक्कोटिल ने अपने खाते से ₹1,01,30,000 और अपनी पत्नी के खाते से अतिरिक्त राशि निकालकर कुल ₹1,16,20,000 की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने अपना एक फ्लैट भी बेचा और उससे प्राप्त राशि को जालसाजों द्वारा दिए गए खातों में स्थानांतरित कर दिया।

बार-बार पैसे वापस करने के अनुरोध के बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर और अधिक धनराशि की मांग की, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। तब पुलिक्कोटिल को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने 25 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पावती संख्या 31902260042239 के तहत पंजीकृत की गई। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के पूर्वी क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके, आपराधिक धमकियों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पीड़ित से पैसे वसूले। आरोपियों का पता लगाने और धोखाधड़ी में शामिल लाभार्थी बैंक खाताधारकों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

गणपतपाटिलनगरमेंजंगलराज; भूमाफियानिरंकुश !

मुंबई : मनपा कार्यलय क्षेत्र के गणपत पाटिल नगर के गली नं 1 से गली नंबर 14 तक चुनाव से पहले व चुनाव के बाद भूमाफिया निरंकुश हो गए हैं। उन्हें किसी शासन प्रशासन का खौफ नहीं रहा। ज्ञात हो कि इस समय गणपत पाटिल नगर अवैध निमार्णों की बाढ़ सी आ गई है। मनपा प्रशासन सिर्फ कागजों पर कार्रवाई कर रहे... हैं।

इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सैकड़ों नोटिस दिए गए हैं उस पर ... आदेश भी दिया जाता है परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय नगर सेवक की भूमिका भी संदिग्ध रही है।

गुंडागर्दी अपने चरम पर है। मनपा, पुलिस और वन विभाग कि लापरवाही से अवैध निर्माण का साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। कच्चे झोपड़ी का रूपांतरण पक्के स्वरूप में किया जा रहा है तथा पक्के अवैध निर्माण का प्रथम मंजिल तक बढ़ाया जा रहा है। खाली पड़ी जमीनों पर बड़े-बड़े व्यावसायिक गाले बनाए जा रहे हैं।

अगर शासन प्रशासन की यही लापरवाही वाला रवैया रहेगा तो यहाँ पूरा जंगलराज स्थापित होने में देर नहीं लगेगा। क्षेत्र में नशे का कारोबार भी फलफूल रहा है। पूर्व में इसी वजह से कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। गुंडे इतने निरंकुश हो गए हैं कि किसी के भी घर में घुसकर मारपीट करना अब आम बात हो चुकी है।

नवी मुंबई : मर्चेंट नेवी भर्ती रैकेट में युवाओं से 20.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी पिता-पुत्र : सीबीडी पुलिस ने मामला दर्ज किया...

नवी मुंबई : एक पिता-पुत्र की जोड़ी ने कथित तौर पर कई शिक्षित युवाओं से मर्चेंट नेवी और शिपिंग सेक्टर में नौकरी दिलाने का लालच देकर 20.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की और फरार हो गए। इसके बाद सीबीडी पुलिस स्टेशन ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

आरोपियों की पहचान वैभव संजय सिंह (32) और उनके पिता संजय सिंह (64) के रूप में हुई है, जिन्होंने छह महीने पहले सीबीडी सेक्टर-11 स्थित रहेजा आर्केड बिल्डिंग में एसएसएस नॉटिकल मरीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कार्यालय खोला था।

पुलिस ने बताया कि दोनों ने मर्चेंट नेवी और शिपिंग उद्योग में काम करने के इच्छुक युवाओं का विवरण एकत्र किया और उन्हें विदेशी जहाजों पर नौकरी दिलाने का लालच दिया। शिकायतकताओं में से एक, दीवा निवासी 23 वर्षीय नहुष नामदेव न्यूग्रे ने नौकरी के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया। जब उन्होंने अपनी नियुक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए बार-बार

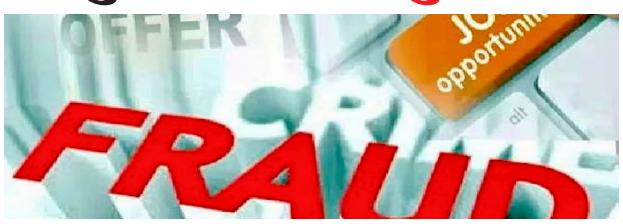

कार्यालय का दौरा किया, तो उन्हें पता चला कि कई अन्य लोग भी ठगे जा चुके हैं।

इनमें उत्तराखंड के ईश्वरसिंह कठायत शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर नॉर्वे में नौकरी के लिए 75 लाख रुपये का भुगतान किया; नवी मुंबई के दीघा निवासी संदीप चव्हाण ने 69,800 रुपये का भुगतान किया; मुंब्रा निवासी मोहम्मद कफील अंसारी ने 70,000 रुपये का भुगतान किया; और उत्तर प्रदेश निवासी दानिश शफीक खान ने मालदीव में नौकरी के लिए 50,000 रुपये का भुगतान किया।

इसके अलावा, आरोपियों ने कथित तौर पर अपने कार्यालय में कार्यरत एक युवक शुभम दारेकर से 10 लाख रुपये उधार लिए थे। जब पीड़ितों ने नौकरी न मिलने पर अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया, तो संजय सिंह ने कथित तौर पर 21 नवंबर, 2025 को स्टांप पेपर पर एक हलफनामा निष्पादित किया, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर सभी को पैसे वापस कर देंगे। हालांकि, कुछ ही देर बाद दोनों ने दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए। सीबीडी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपियों ने शिपिंग क्षेत्र में विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया। हम उनके वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या और भी पीड़ितों को ठगा गया है। दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढकर गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।''

संपादकीय

विवादों में शंकराचार्य

शंकराचार्य भारत की अनोखी त्याग परंपरा का विस्तार हैं। आदि शंकराचार्य ने विश्व दर्शन को अद्वैत दर्शन से समृद्ध किया। अल्प आयु में ही उन्होंने 11 प्रमुख उपनिषदों, गीता और ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। सांस्कृतिक एकता के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। बौद्ध एवं अन्य विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्हें सभी स्थानों पर विजय मिली। शंकराचार्य के भ्रमण को उस समय दिग्विजय कहा गया। उन्होंने सांस्कृतिक विचारधारा को प्रवाहमान बनाने के लिए चार मठों की स्थापना की। कर्नाटक में शृंगेरी, उत्तराखंड में जोशीमठ, ओडिशा में पुरी और गुजरात में द्वारका। उनके चार विद्वान शिष्यों ने मठों का नेतृत्व किया। उन्होंने चारों वेदों को प्रतिष्ठा दी। सभी मठों को एक वेद से जोड़ा-शृंगेरी पीठ, कर्नाटक-यजुर्वेद, द्वारका पीठ, गुजरात-सामवेद, पुरी पीठ, ओडिशा-ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड-अथर्ववेद। वे द्रष्टा थे। अद्वैत वेदांत उनका दर्शन था। डॉ. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था। दुर्भाग्य से आधुनिक काल के शंकराचार्य अपने कार्य व्यवहार से निराश करते हैं। वे प्रेरित नहीं करते। उत्साह और उल्लास नहीं देते। वे व्यापक हिंदू समाज को कोई ठोस एवं प्रभावी दिशा नहीं देते। इन दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन और शासन से विवाद के कारण लगातार चर्चा में हैं। इस विवाद की शुरूआत प्रयागराज में माघ मेले में स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव से हुई थी। मौनी अमावस्या पर्व पर स्वामी जी पारंपरिक पालकी से स्नान के लिए निकले।

प्रशासन ने उनका ध्यान भीड़ प्रबंधन की ओर आकर्षित किया और उनसे पैदल चलने का अनुरोध किया। इसके बाद उनके अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। आचार्य के अनुयायियों के अनुसार शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। स्वामी जी ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया और बिना स्नान किए लौट आए। प्रशासन ने स्वामी जी को लिखित चेतावनी दी। नोटिस में उन पर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन आदेश का उल्लेख करते हुए पूछा गया कि वे अपने शिविर के बाहर बोर्ड पर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं?

पता नहीं इस विवाद का पटाक्षेप कैसे और कब होगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि हम भारत के लोग साधु-संतों को सम्मान से देखते हैं। गीता में संन्यासी की परिभाषा है, 'जो इच्छारहित है, सभी द्वंद्वों से मुक्त है, वही संन्यासी है।' आदि शंकराचार्य ऐसे ही दार्शनिक संन्यासी थे। साधना की सिद्धि प्राप्त संत हैं। महतत्व के बोध वाला महंत है, लेकिन आज के शंकराचार्य संभवतः ऐसा नहीं मानते। वे स्वयं के सम्मान के लिए झगड़ा करते हैं। कोर्ट-कचहरी में पदों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा पहले से भी होता आ रहा है। मठों-पीठों की संपदा को लेकर भी झगड़े होते रहे हैं और वे अंग्रेजी राज में ही प्रिवि काउंसिल तक जा चुके थे। पीवी काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में लिखा है कि मठों में अधिकार क्षेत्र आदि को लेकर झगड़े होते रहे हैं। प्रथम शंकराचार्य ने मठों के संचालन के लिए 'मठाम्नाय महानुशासन' की नियमावली बनाई थी। मठाम्नाय का अर्थ है महानुशासन। शंकराचार्य दर्शन और अध्यात्म के परम विद्वान थे। उन्होंने काम करते हुए अनुभव कर लिया था कि सांसारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में संलग्न व्यक्ति धर्म प्रचार का कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने संसार त्यागी सुयोग्य ब्रह्म पारायण संन्यासियों को धर्म प्रचार का कार्य सौंपा और सबके लिए अनुशासन पालन का नियम बनाया। शंकराचार्यों को उससे शासित होना चाहिए। आश्चर्य है कि हमारे शंकराचार्य कुंभ या अन्य अवसरों पर पहले स्नान के लिए झगड़ते हैं। राजनीतिक मामलों में वक्तव्य देते हैं। धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देते हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अंतरराष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन यह आयोजन राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। इसका कारण कुछ शंकराचार्यों के बयान रहे।

संपादकीय कार्यालयः
आर. जे. पब्लिकेशन के लिए मुद्रक, प्रकाशक, मालिक राजू ज. पंडित द्वारा हनुमान कंपाउंड, एस.एन. दुबे रोड, रावल पाडा, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400068 से प्रकाशित व भारत लिथो एवं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस : 48, गुलशन महल कंपाउंड, फारस रोड, मुंबई - 400008 से मुद्रित। संपादक : राजू ज. पंडित
संपर्क कार्यालय : संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो.लि. एसएन दुबे रोड रावल पाड़ा दहिसर (पूर्व) मुंबई 400068

संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो. लि., एस एन दुबे रोड
रावलपाड़ा दहिसर पूर्व मुंबई ४०००६८
Mob No. : 9967776303
RNI : MAHHIN/2003/10991

डोंबिवली : पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट ने म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए ₹2.6 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का आरोप लगाया

डोंबिवली : डोंबिवली की एक पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि उसके बैंक अकाउंट से बिना उसकी जानकारी के ₹2.6 करोड़ के फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए गए। यह उत्तराखंड में पीड़ितों से जुड़ा एक बड़ा साइबर फ्रॉड लगता है। स्टूडेंट ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पिछले तीन महीनों में बार-बार बताने के बावजूद पुलिस ने उसकी शिकायत पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया।

अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के आरोप

स्टूडेंट, जिसकी पहचान निधि तिवारी के तौर पर हुई है, डोंबिवली के गोग्रासवाड़ी की रहने वाली है। वह अभी कल्याण के एक जाने-माने कॉलेज से टू की डिग्री कर रही है। उसकी शिकायत के मुताबिक, उसकी एक दोस्त, चांदनी सिंह, जो फ्छ बैंक में काम करती है, ने उसे नए अकाउंट खोलने के लिए इंटरनल टारगेट का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट खोलने के लिए मनाया। तिवारी ने आरोप लगाया कि सिंह ने प्रोसेस में मदद करते हुए उसे कुछ पैसे दिए और भरोसा दिलाया कि अकाउंट रेगुलर बैंकिंग प्रोसेस के तहत खोला जा रहा है। हालांकि, कुछ महीने बाद, उसे यह जानकर झटका लगा कि उसके अकाउंट से ₹2.6 करोड़ के ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुके थे। इसके अलावा, उसके नाम पर खोले गए एक और अकाउंट में कथित तौर पर करीब ₹10 लाख के ट्रांजैक्शन हुए। सिंह से पूछताछ करने पर, तिवारी ने दावा किया कि उन्हें गोलमोल जवाब मिले। आगे की पूछताछ में कथित तौर पर पता चला कि साइबर फ्रॉड स्कीम के जरिए उत्तराखंड के लोगों से पैसे निकाले गए थे और कहीं और भेजने से पहले कुछ समय के लिए उसके अकाउंट में रखे गए थे।

पुलिस कंप्लेंट और पॉलिटिकल दखल स्टूडेंट ने पुलिस को इस रैकेट में उल्हासनगर के एक व्यक्ति के कथित तौर पर शामिल होने की भी जानकारी दी। डिटेल्स जमा करने और करीब तीन महीने तक फॉलो-अप करने के बावजूद, उसने आरोप लगाया कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले ने अब पॉलिटिकल मोड़ ले लिया है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर अविनाश जाधव ने मामले में दखल दिया है। जाधव ने पुलिस की कथित तौर पर कोई कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाए। जाधव ने कहा, ''जबकि मुख्यमंत्री साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के बड़े-बड़े दावे करते हैं, डोंबिवली के एक स्टूडेंट और उत्तराखंड के पीड़ितों से जुड़ा एक गंभीर अपराध सामने आया है। फिर भी, पुलिस कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है।'' उन्होंने आगे सवाल किया कि एक कथित संदिग्ध, जिसे कथित तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसे बिना किसी और कार्रवाई के क्यों छोड़ दिया गया।

मुंबई : स्वच्छता रैंकिंग में ठाणे जेपी का उत्कृष्ट प्रदर्शन

मुंबईः संत गाडगे बाबा के स्वच्छता के विचारों पर आधारित संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत साल 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के स्पर्धा में चुनी गई ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 25 फरवरी 2026 को कोंकण संभाग के संभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी की अध्यक्षता में सिडको कार्यालय सभागृह , , सिडको भवन, बेलापुर, नवी मुंबई में हुआ। इस मौके पर ज़िला परिषद, ठाणे के तहत बहुत अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साल 2022-23 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत डिविजन लेवल के कॉम्पिटिशन में, ग्राम पंचायत वडपे (तेल. भिवंडी) ने दूसरा स्थान हासिल किया और उसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और 9 लाख रुपये का चेक मिला। इसी तरह, ग्राम पंचायत जांभुल (तेल. कल्याण) ने तीसरा स्थान हासिल किया और उसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला।

इसी प्रोग्राम में, महा आवास अभियान 2023-24 के तहत स्टेट स्पॉन्सर्ड घरकुल स्कीम को अच्छे से लागू करने के लिए ज़िला परिषद ठाणे को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट - थर्ड प्लेस का अवार्ड दिया गया। राज्य प्रायोजित आवास योजना 2023-24 के अंतर्गत मणिवाली ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला। इस सफलता के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, परियोजना निदेशक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जल एवं स्वच्छता विभाग) पंडित राठौड़ के साथ ही सभी समूह विकास अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम को हार्दिक बधाई दी गई।

इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि ठाणे जिले ने स्वच्छता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगातार और प्रभावी प्रदर्शन करके राज्य और संभाग स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। भविष्य में भी इसी तरह जनभागीदारी से विकास कार्यों को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

मुंबई : AIMIM नेता वारिस पठान ने नमाज पर FIR और धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल

मुंबई : AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, ''अगर रमजान का महीना है और नमाज का वक्त हो गया और किसी ने नमाज पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।'' वारिस पठान ने धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कौन से कानूनी प्रावधान के तहत नमाज़ियों पर FIR दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक पक्षपाती रवैया है और इसका मकसद केवल नफरत फैलाना है।

पठान ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकारी दफ्तर में किसी धार्मिक आयोजन पर रोक लगानी है, तो यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी एक समुदाय के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग नियम बनाना गलत है। वारिस पठान का बयान राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक समानता और संविधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। उनका मानना है कि सरकार का रवैया धार्मिक विविधता को स्वीकार करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बयान से न केवल मुस्लिम समुदाय में समर्थन बढ़ा है, बल्कि यह मुद्दा देश में धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की समानता पर बहस का विषय बन गया है। AIMIM नेता का यह विरोधी रुख आगामी चुनावों और समाज में धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है।

मुंबई : एयरपोर्ट पर नहीं अदा कर पाएंगे नमाज...

सरकार ने बताई वजह; दिया ये विकल्प

मुंबई : एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की नमाज अदा करने की मांग सुरक्षा कारणों के चलते खारिज कर दी गई है. राज्य सरकार और टटफ्लअ ने एयरपोर्ट के बाहर शेड में नमाज की अनुमति देने में असमर्थता जताई थी. हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने वैकल्पिक स्थान खोजने पर विचार करने को कहा है, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चालकों को पास की मस्जिदों में जाने का सुझाव दिया गया है.

मुम्बई के एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने मांग की थी. जबकि बीजेपी और उसके नेता शुरूआत से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं. इसको लेकर विधानसभा में भी जमकर बहस देखने को मिली थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकाई ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा था. एमएमआरडीए ने कोर्ट में अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति देना किसी भी हालत में संभव नहीं है. राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि टेक्सी और कैब ड्राइवर्स नजदीकी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

क्या है वजह जो नहीं मिली इजाजत?

मुंबई हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि

सुरक्षा कारणों से छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (सीएसएमआईए) के बाहर शेड बनाकर रमजान और अन्य दिनों में ऑटो, टैक्सी, ओला-उबर चालकों को नमाज अदा करने की अनुमति देना संभव नहीं है.

कोर्ट का राज्य सरकार और एमएमआरडीए को निर्देश

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पुनिवाला की बेंच ने राज्य सरकार और एमएमआरडीए को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट परिसर के भीतर ही कोई वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने की संभावना पर विचार करें, ताकि रमजान के दौरान चालक और यात्री नमाज अदा कर सकें. इससे पहले की सुनवाई में बेंच ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता ऑटो-टैक्सी, ओला-उबर मेन्स यूनियन की मांग पर विचार करने की सलाह एमएमआरडीए को दी थी.

राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अदालत को बताया कि संबंधित क्षेत्र हाई-सिक्योरिटी जोन है. वहां संभावित खतरे की आशंका बनी रहती है. एयरपोर्ट और आसपास के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है.

याचिकाकताओं के अनुसार, प्रतिदिन पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है, जिसमें 1500 से 2000 लोग शामिल होते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के दिन में पांच बार एकत्र होने से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा.

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकानी ने दलील दी कि प्रस्तावित स्थान के पास ही तीन मस्जिद मौजूद हैं. इनमें से एक मस्जिद लगभग एक किलोमीटर दूरी पर है, वहां पैदल 13 मिनट में पहुंचा जा सकता है. दूसरी मस्जिद 1.3 किलोमीटर दूर है, जहां 18 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जबकि तीसरी मस्जिद 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

मुंबई : कक्षा 1 से 10 तक BEST बस यात्रा मुफ्त

मुंबई : मुंबई शहर के लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीएमसी ने अपने बजट 2026-27 में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को इएरळ की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य परिवारों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम करना और विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक आने-जाने को आसान व सुरक्षित बनाना है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, यह योजना मुंबई के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर लागू होगी। योजना के तहत विद्यार्थियों को बस पास के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी जिनके दो या उससे अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं और रोजाना बस से सफर करते हैं।

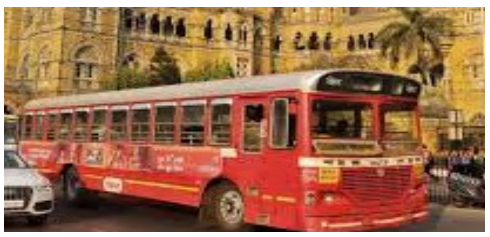

शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

नगर निगम का कहना है कि कई परिवारों के लिए रोजाना यात्रा का खर्च एक बड़ी चिंता होती है। बस किराया, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्च मिलाकर शिक्षा का कुल खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में यह कदम छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। अधिकारियों का मानना है कि जब यात्रा की चिंता कम होगी, तो विद्यार्थी समय पर और सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच सकेंगे।

सार्वजनिक परिवहन को भी मिलेगा प्रोत्साहन

इस योजना से बच्चों में कम उम्र से ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की आदत विकसित होगी। इससे भविष्य में निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और ट्रैफिक तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। इएरळ प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुविधा के लिए आवश्यक पास और पहचान पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

हजारों छात्रों को होगा लाभ

अनुमान है कि इस योजना से मुंबई के हजारों छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। कई अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनके मासिक खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी।

कब से लागू होगी योजना?

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, योजना को शैक्षणिक सत्र 2026झ27 से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। स्कूल प्रशासन को भी छात्रों का डेटा साझा करने और पास वितरण की प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा जाएगा। मुंबई महानगरपालिका का यह कदम छात्र कल्याण की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल शिक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुंबई : मध्य रेलवे ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई यात्री सुविधाएं, लगाए गए नए लिफ्ट, एस्केलेटर, पंखे और डिस्प्ले बोर्ड

मुंबई : मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जनवरी 2026 के दौरान मुंबई मंडल के कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। इन कार्यों का उद्देश्य सभी यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई मंडल में कुल 4 नए एस्केलेटर लगाए गए हैं। इनमें कसारा स्टेशन पर 2 और बदलापुर स्टेशन पर 2 एस्केलेटर शामिल हैं। इसके अलावा 2 नई लिफ्ट भी शुरू की गई हैं, जिसमें एक वांगनी स्टेशन और एक बदलापुर स्टेशन पर स्थापित की गई है। इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं,

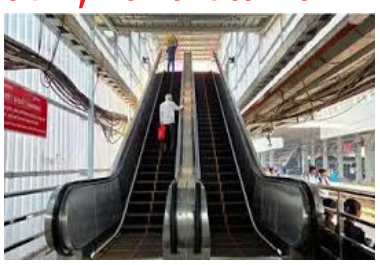

दिव्यांगजनों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को प्लेटफार्म बदलने में काफी सहूलियत मिली है।

लगाए गए बिजली बचाने वाले पंखे...

यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेशनों पर 142 नए बीएलडीसी पंखे लगाए गए हैं, जबकि 289 पुराने पंखों को नए बीएलडीसी पंखों से बदला गया है। ये पंखे कम बिजली खपत करते हैं और पारंपरिक पंखों की तुलना में 50 से 70 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत करते हैं। इसके साथ ही दादर स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर 8 नए हाई वॉल्यूम लो स्पीड (एचवीएलएस) पंखे लगाए गए हैं, जो बड़े क्षेत्र में बेहतर वेंटिलेशन और ठंडक प्रदान करते हैं। ऊर्जा बचत और बेहतर प्रकाश व्यवस्था के तहत मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 362 नई एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। साथ ही 1635 पुरानी एलईडी लाइटों को नई और अधिक प्रभावी लाइटों से बदला गया है। इससे न सिर्फ रोशनी बेहतर हुई है, बल्कि रखरखाव लागत में भी कमी आई है।

मुंबई : NCP संसदीय बोर्ड ने पार्थ पवार को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया

मुंबई : NCP के विधायक धनंजय मुंडे ने पुष्टि की है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पार्थ पवार को राज्यसभा की खाली होने वाली सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट सुनेत्रा पवार के हालिया राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। धनंजय मुंडे ने कहा, ''वाहिनी के इस्तीफे के बाद, राज्यसभा सीट खाली होने वाली थी। हमारे संसदीय बोर्ड ने पार्थ पवार के नाम पर फैसला किया है। दादा (अजीत पवार) आज हमारे बीच नहीं हैं। इसलिए, पार्टी

को न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया।''

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय पार्टी की सुदृढ़ीकरण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें युवाओं और अनुभवी नेताओं के मिश्रित नेतृत्व के माध्यम से पार्टी की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना शामिल है।

मुंडे ने कहा कि पार्थ पवार की राज्यसभा सदस्यता से पार्टी को रणनीतिक लाभ मिलेगा और भविष्य में विभिन्न मुद्दों पर मजबूत स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में NCP का यह कदम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर सही उम्मीदवार के चयन से पार्टी के संसदीय प्रभाव और महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। संसदीय बोर्ड का यह निर्णय अजीत पवार की अनुपस्थिति में पारिवारिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पार्थ पवार की राज्यसभा सदस्यता पर जल्द ही औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। NCP के नेताओं का मानना है कि यह कदम पार्टी की राष्ट्रीय राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और आगामी चुनावों में रणनीतिक लाभ दिलाने में सहायक होगा।

अवैध निर्माण विवाद : यूसुफ हाइट्स की फाइलें कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड रूम से गायब, फोरेंसिक जांच शुरू...

कल्याण : कल्याण में यूसुफ हाइट्स से जुड़ा हाई-प्रोफाइल अवैध कंस्ट्रक्शन का विवाद तब और बढ़ गया जब प्रोजेक्ट से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स कथित तौर पर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड रूम से गायब हो गए। सिविक बॉडी के हेडक्वार्टर से ऑफिशियल फाइलों के गायब होने से एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों में चिंता बढ़ गई है और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के कामकाज की जांच तेज हो गई है।

गायब अप्रूवल और रिकॉर्ड

सूत्रों के मुताबिक, गायब डॉक्यूमेंट्स यूसुफ हाइट्स से जुड़े अप्रूवल और रिकॉर्ड से जुड़े हैं, यह बिल्डिंग पहले से ही रिजर्व जमीन पर कथित अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर विवादों में है। यह मामला तब सामने आया जब बार-बार इंटरनल सर्च के बावजूद म्युनिसिपल रिकॉर्ड रूम में फाइल नहीं मिली। इसके तुरंत बाद, इस मामले को ऑफिशियली आगे बढ़ाया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, राज्य के होम डिपार्टमेंट की एक फोरेंसिक टीम ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया और पूरी जांच शुरू की। खबर है कि टीम ने रिकॉर्ड रूम पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया, रजिस्टरों की जांच की, डॉक्यूमेंट एंट्री वेरिफाई कीं, और सेक्शन में और उसके आसपास लगे उउळश फुटेज को स्कैन किया।

शुरूआती जांच के तहत कई अधिकारियों और कर्मचारियों, खासकर टाउन प्लानिंग विंग के लोगों से पूछताछ की गई। जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि क्या फाइल प्रोसेस में हुई चूक की वजह से खो गई थी या जरूरी सबूतों को दबाने के लिए जानबूझकर हटाई गई थी। और भी फाइलें शक के दायरे में सूत्रों का यह भी दावा है कि यह मामला शायद किसी एक फाइल तक सीमित नहीं है। एक और विवादित स्ट्रक्चर, मरियम टावर से जुड़े डॉक्यूमेंट भी गायब बताए जा रहे हैं।

बिल्डिंग की दो जरूरी फाइलों के गायब होने की खबर ने शक को और गहरा कर दिया है और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जांच के दायरे में आ गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों ने गंभीर लापरवाही या मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया है। इस हफ्ते की शुरूआत में बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में गायब डॉक्यूमेंट्स के बारे में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि टाउन प्लानिंग सर्वेयर कुणाल शसाने का बयान दर्ज किया गया है, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने संबंधित फाइलें डिपार्टमेंट में अपने सीनियर अधिकारियों को सौंप दी थीं। जांच आगे बढ़ने पर दूसरे अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।

यूसुफ हाइट्स के अलावा, एक और प्रोजेक्ट, खट टावर पर भी रिजर्व जमीन पर कंस्ट्रक्शन के आरोप लगे हैं। सिविक बॉडी ने पहले बिल्डर सलमान अनीश डोलारे और उसके साथियों के खिलाफ टफळढ एक्ट के तहत दो केस दर्ज किए थे। इसके अलावा, फ्लैट खरीदने वालों ने डेवलपर के खिलाफ धोखाधड़ी की तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, बिल्डर के खिलाफ अभी कम से कम छह केस दर्ज हैं, जो कथित तौर पर फरार है। म्युनिसिपल हेडक्वार्टर के अंदर से सेंसिटिव फाइलों के गायब होने से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गायब रिकॉर्ड असरदार लोगों के हितों को बचाने या चल रही कानूनी कार्रवाई को कमजोर करने की कोशिश की ओर इशारा कर सकते हैं।

मुंबई : वडेट्टीवार: कांग्रेस की नजर राज्यसभा सीट पर, महाविकास अघाड़ी मीटिंग में भी अपनी बात रखी

मुंबई : आने वाले राज्यसभा चुनाव में राज्य की विपक्षी पार्टियों महाविकास अघाड़ी को सिर्फ.एक सीट मिलने की संभावना है। यह अकेली सीट है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा। महाविकास अघाड़ी में घटक पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। इसी पृष्ठभूमि में महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस राज्यसभा सीट पर फैसला किया गया।

कांग्रेस को राज्यसभा सीट दिलाने पर अड़ी कांग्रेस के नेताओं ने सहमति जताई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए महाविकास अघाड़ी की स्थिति साफ की।

चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है कि राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलनी चाहिए। बैठक में ठउढ और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दोनों ने अपने विचार रखे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि ठउढ शरद पवार पार्टी के नेता इस बारे में अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे, जबकि उद्धव सेना भी अपनी स्थिति साफ करेगी।

एयरपोर्ट कस्टम्स ने यात्रियों द्वारा छोड़ी गई धार्मिक चीजें संबंधित समुदायों को सौंपी

मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल यात्रियों द्वारा छोड़े गए धार्मिक ग्रंथों, पवित्र वस्तुओं और यादगार वस्तुओं को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके संबंधित धार्मिक समुदायों को सौंपने की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत, चेंबूर के एक वेलफेयर ट्रस्ट को 35 कृपाण और एक चर्च को चार बाइबिल सौंपी गईं। कस्टम्स सूत्रों ने बताया कि धार्मिक वस्तुओं को इस महीने की शुरूआत में सौंपा गया था।

एक कस्टम अधिकारी ने कहा, ''छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम्स जोन-III ने इंटरनेशनल यात्रियों द्वारा छोड़े गए धार्मिक ग्रंथों, पवित्र वस्तुओं और यादगार वस्तुओं को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके संबंधित धार्मिक समुदायों को

सौंप दिया है। इस पहल में, 'सत श्री अकाल वेलफेयर ट्रस्ट' को 35 कृपाण और 'न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च' को चार पवित्र बाइबिल सौंपी गईं, जिसके लिए दोनों संस्थाओं ने डिपार्टमेंट की तारीफ की।'' सत श्री अकाल वेलफेयर ट्रस्ट ने मुंबई के उरटक एयरपोर्ट के चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को लिखे एक लेटर में सिख धर्म से जुड़ी धार्मिक चीजों को इज्जतदार और सम्मान के साथ सौंपने के दौरान कस्टम्स डिपार्टमेंट के शानदार सहयोग, सपोर्ट और समझ के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों की तारीफ की।

एक कस्टम अधिकारी ने कहा, ''छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम्स जोन-III ने इंटरनेशनल यात्रियों द्वारा छोड़े गए धार्मिक ग्रंथों, पवित्र वस्तुओं और यादगार वस्तुओं को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके संबंधित धार्मिक समुदायों को सौंप दिया है। इस पहल में, 'सत श्री अकाल वेलफेयर ट्रस्ट' को 35 कृपाण और 'न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च' को चार पवित्र बाइबिल सौंपी गईं, जिसके लिए दोनों संस्थाओं ने डिपार्टमेंट की तारीफ की।''

सत श्री अकाल वेलफेयर ट्रस्ट ने मुंबई के CSMI एयरपोर्ट के चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को लिखे एक लेटर में सिख धर्म से जुड़ी धार्मिक चीजों को इज्जतदार और सम्मान के साथ सौंपने के दौरान कस्टम्स डिपार्टमेंट के शानदार सहयोग, सपोर्ट और समझ के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों की तारीफ की। ट्रस्ट के चेयरमैन एस. पूरन सिंह बंगा की तरफ से दिए गए लेटर में कहा गया, ''ट्रस्ट उनके प्रोफेशनलिज्म, सेंसिटिविटी और कल्चरल अवेयरनेस को दिल से मानता है और उनकी तारीफ करता है, जो धार्मिक भावनाओं और मूल्यों के लिए एक तारीफ के काबिल सम्मान दिखाता है।